

राजस्थान के बजट में दिखा मोदी विजन



रमेश सरफ घनात्रा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश किए गए भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय पर तरह से आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर लोक लुभावा बनाया गया है। हालांकि अंतिम बजट होने के कारण इसमें अधिक घोषणाएं नहीं की गई हैं। फिर भी बजट में ऐसी अन्य को बातों को शामिल किया गया है जिसका अपना सीधे आप लोगों पर पड़ा है।

विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा गया है। अनुभव के हिसाब से उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वित्तमंत्री के रूप में पहला बजट पेश किया था। मगर जिस तरह से उन्होंने बजट भाषण पढ़ा उसमें पूरा आनंदविश्वास झलक रहा था।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार का वह पहला बजट था।

इस कारण उनके बाद सरकार के दौरान किए गए लोक लुभावने की विजय में शामिल किया गया है। बहुत जरूरी था। उसी को ध्यान में रखते हुए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने बजट में महिलाओं, बुजुर्गों, युवाओं, किसानों, व्यापारियों, धमार्चार्यों को खुश करने के लिए बजट में कई तरह के प्रवाधन किए हैं। प्रदेश में बुजुर्गों को अपनी तक रोडवेज की बासों में 30 प्रतिशत किया गया है। इसी तरह 50 प्रतिशत कर दिया गया है। इसी तरह नागरिकों को मिलने वाली सामाजिक सुक्ष्मा मासिक फैशन के लिए हजार रुपए से बढ़ाकर 1150 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

उपमुख्यमंत्री ने बजट में 70 हजार युवाओं को नई नौकरी देने की घोषणा की है। इसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग वर राजस्थान कम्बारी चम्बा बोर्ड के द्वारा भर्ती कैलेंडर भी बनाने की बात कही गई है। राजस्थान में पिछली अंगठी गहलोत सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा भर्ती परीक्षाओं में हो रही धांधली को लेकर था। गहलोत सरकार के कायवाल में 18 भर्ती परीक्षाओं के पेपर लोक होने के कारण परीक्षाओं के निरसन करना पड़ा था। बाद में प्रशासनिक परीक्षाओं में भी कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के विचारन को लेकर विवाद हुआ था। जिसके चलते आम जन में गहलोत सरकार की नकारात्मक छवि बनी थी।



इस बात को ध्यान में रखकर भाजपा सरकार ने अपने पहले ही बजट में युवाओं को लुभाने के लिए एक साथ 70 हजार नयी भर्तीयों की घोषणा की है। हालांकि भाजपा ने चुनाव से पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग में आपूर्त चूल्हा परिवर्तन करने की बात भी कही थी। मगर उस पर अपनी तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। भाजपा को पता है कि प्रदेश में युवा मासिताओं की बढ़ाती ही उनकी सरकार बन पाई है। ऐसे में उन्हें अपने साथ जोड़े रखना बहुत जरूरी है।

सर्विदा पर काम कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिन, सहायिकाओं के साथ ही अन्य सर्विदा कार्यमयों तथा पंचायती राज व नगरीय निकायों के निवाचित जन प्रतिनिधियों को मिलने वाले मासिक भर्ते में 10 प्रतिशत बढ़ावाली की घोषणा की गई है। प्रदेश में इसका बड़ा अपर होगा तथा कई लाख लोगों को इस बढ़ोतारी का लाभ पायेगा। जिससे अगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को फायदा पायेगा। अपने बजट भाषण के दौरान जब कुमारी को टोके रहे थे तो उन्होंने धारीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं है। यहां पर

महिलाएं भी बगबार की संख्या में हैं। उनके पास भी बोट की शक्ति है। इसी के चलते राज्य सरकार ने अपने अंतिम बजट में महिलाओं के हित की कई योजनाओं की घोषणा कर उन पर पूरा फोकस रखा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक करोड़ नई लखपति दीदी बनाने की घोषणा की थी। उनकी की तर्ज पर राजस्थान के बजट में भी 5 लाख परिवारों की महिलाओं दीदी बोट की शक्ति दीदी योजना में सामिल कर उनकी आय की एक लाख से अधिक बढ़ाया जाएगा। गरीब परिवर्गों में कट्टा के जम्म पर

एक लाख रुपए का सेविंग बांड दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मात्र बंदन योजना में प्रथम प्रसव पर 6 हजार रुपए दिए जाएंगे। जबकि अपनी तक वह राशि पांच हजार थी। प्रदेश के लोगों के सभी बॉर्डों में एक-एक आर्स आंगनबाड़ी के द्वारा दीदी बोट की शक्ति दीदी योजना में निराशा व्याप्त हुई है। इससे अमरनाथ जनकी का गहलोत नाम दीदी बोट की शक्ति दीदी योजना में निराशा व्याप्त हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए के लोगों को 300 योग्यतावाले लोगों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा। जिससे उपर्युक्त विवरणों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर का डे केर इलाज की शक्ति दीदी योजना में आपूर्त राजस्थान के 5 लाख धर्मीयों के लिए एक लाख रुपए दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सभी चुनावी जनसभाओं में प्रदेश में पेश कर दिया था। मगर राज्य सरकार के बजट में उस पर कोई विवाद नहीं हो पाया है। जिसमें केसर क

प्लास्टिक गोदाम पर छापा मारकर ३४१० किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त

नगर निगम के उथना जोन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण के लिए दंड की कार्यवाही शुरू

प्रतिबंध के बावजूद शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक डंप किया जा रहा है

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

सूरत नगर निगम ने एक बार फिर प्रतिबंधित प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल नगर निगम छोटे बाजारों के बजाय प्रतिबंधित प्लास्टिक सप्लाई करने वाली एजेंसियों या गोदामों पर छापेमारी कर रही है। जिसके तहत आज नगर पालिका ने



उथना क्षेत्र में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की कार्यवाही शुरू कर दी

है।

सूरत नगर निगम क्षेत्र में १२० माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध है। हालांकि, यह प्रतिबंधित प्लास्टिक अभी भी सूरत में आसानी से उपलब्ध और उपयोग किया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका सब्जी बाजार या लौसी विक्रेताओं और मर्मटों पर कार्रवाई करती थी और उन पर जुर्माना लगाती थी। नगर निगम का प्रतिबंध लागू नहीं किया गया क्योंकि काब्यद शुरू कर दी

बड़े व्यापारी और आपूर्तिकर्ता शहर में प्रतिबंधित प्लास्टिक की तस्करी करते थे। पिछले कुछ समय से नगर निगम ने प्रतिबंधित प्लास्टिक सप्लाई करने वाली एजेंसियों या गोदामों पर छापेमारी शुरू कर दी है। जिसके तहत आज उथना क्षेत्र के एक गोदाम से ३४१० किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक बरामद हुआ, नगर निगम ने इस प्लास्टिक को जब्त कर दंडात्मक कार्रवाई की काब्यद शुरू कर दी है।

एमएसएमई के नए नियमों को लेकर व्यापारिक संगठनों ने दिल्ली में वित्त मंत्री से की मुलाकात

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

वित्त मंत्री ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया की व्यापारियों के हित में है। और साथ ही इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। कैलास हाकिम ने निम्न मुद्दों पर वित्तमंत्री से बातचीत की। इस नियम के १ वर्ष के लिए स्थगित करने का निवेदन किया। एमएसएमई के नियम



में छोटे बड़े सभी घटकों का समावेश किये जाने की बात रखी।

एमएसएमई में पेमेंट करने की जो समय अवधि दि गई उसे बढ़ाने के बात कही गई। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण से विभिन्न व्यापारी संगठन द्वारा एमएसएमई ४३ (बी) के नये नियम के सन्दर्भ में मुलाकात की गई।

फोस्टा अध्यक्ष कैलाश ने सभी मुद्दों को ध्यान से सुना एवं भरोसा दिलाया कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा व्यापारियों के हित में नीति बनाने का भरोसा दिया। एमएसएमई के नए आयकर के मामले में सूरत कपड़ा मार्केट सहित देश में भी उलझन बढ़ गई थी। कपड़ा मंडी में इस चिंता का नियकरण भी उसी के हाथ में है, जिसने आयकर प्रावधान को लागू किया। एमएसएमई के प्रावधान से पैदा हुई मुश्किलें से कपड़ा क्रय क्रिय प्रणाली पर भारी असर देखने को मिला रहा है। कपड़ा बाजार इस समय गुलजार रहता था। वही मार्केट में सनाता पसरा हुआ है। कारोबार में काफी असर देखने को मिल रहा है। कपड़ा

देश का पहला 'साइकिल टू स्कूल' प्रोजेक्ट

नगर निगम की लापरवाही के कारण खटाई में पड़ सकता है

सिटी लाइट स्कूल के 'साइकिल टू स्कूल' प्रोजेक्ट के लिए ट्राफिक कोन टूट गए

साइकिल से स्कूल जाने के लिए बने ट्रैक के किनारे अवैध स्पैस से अतिक्रमण कर अस्थाई दुकानें बना ली गई

क्रांति समय

www.krantisamay.com
www.guj.krantisamay.com
www.epaper.krantisamay.com
www.rti.krantisamay.com

देश का पहला साइकिल टू स्कूल प्रोजेक्ट सूरत शहर में शुरू हो गया है और क्यायास लगाए जाने लगे हैं कि नगर निगम की लापरवाही से खटाई में पड़ सकता है। सूरत नगर निगम ने सिटी लाइट के एक स्कूल में साइकिल से स्कूल तक प्रोजेक्ट शुरू किया है, अभी एक महीना भी नहीं हुआ है लेकिन इस साइकिल ट्रैक के लिए लगाए गए ट्रैफिक कोन टूट गए हैं। ट्रैक पर वाहन पार्क किए जाते हैं और कुछ फुटपाथ पर दुकानें खोल दिए गए हैं। देश भर के १०० स्मार्ट शहरों में से केवल सूरत शहर को लाइट स्कूल ट्रैक के लिए चुना गया है और यह प्रोजेक्ट ८ जनवरी को



शुरू किया गया है।

हालांकि, इस साइकिल टू स्कूल प्रोजेक्ट को शुरू हुए बमुश्किल एक महीना ही हुआ है, लेकिन साइकिल ट्रैक के लिए जगह ही है। हालांकि देश की बनाने के लिए लगाए गए कई सूरत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा 'साइकिल टू स्कूल' के पायलट प्रोजेक्ट के लिए सिटी लाइट क्षेत्र में स्कूल कीलों से साइकिल चलाने वाले विद्यार्थियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इसके अलावा, ट्रैफिक कोनों से निकली गए ट्रैफिक सेस की कमी है, इसके अलावा ट्रैफिक कोन टूट हुए हैं और इस मार्ग पर दबाव के कारण अल्टावा, परियोजना के लिए बनाया गया है।

इसलिए साइकिल ले जाने वाले छात्रों के साथ दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि देश की बनाने के लिए जगह ही है, लेकिन साइकिल ट्रैक के लिए जगह ही है। हालांकि देश की बनाने के लिए लगाए गए कई सूरत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा 'साइकिल टू स्कूल' के पायलट प्रोजेक्ट के लिए सिटी लाइट क्षेत्र में स्कूल कीलों से साइकिल चलाने वाले विद्यार्थियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इसके अलावा, ट्रैफिक कोनों से निकली गए ट्रैफिक सेस की कमी है, इसके अलावा ट्रैफिक कोन टूट हुए हैं और इस मार्ग पर दबाव के कारण अल्टावा, परियोजना के लिए बनाया गया है।

चूंकि नगर निगम ने साइकिलों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ दिया है, लेकिन ट्रैक पर वाहन पार्क करते हैं। इसलिए कुछ लोग ट्रैक पर दबाव लगाए गए हैं। इन ट्रैक पर गाड़ियां खड़ी कर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

चूंकि नगर निगम ने साइकिलों को जीपीएस सिस्टम से जोड़ दिया है, लेकिन ट्रैक पर वाहन पार्क करते हैं। इसलिए कुछ लोग ट्रैक पर दबाव लगाए गए हैं। इन ट्रैक पर गाड़ियां खड़ी कर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

इसलिए साइकिल ले जाने वाले छात्रों के साथ दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि देश की बनाने के लिए लगाए गए कई सूरत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा 'साइकिल टू स्कूल' के पायलट प्रोजेक्ट के लिए सिटी लाइट क्षेत्र में स्कूल कीलों से साइकिल चलाने वाले विद्यार्थियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इसके अलावा, ट्रैफिक कोनों से निकली गए ट्रैफिक सेस की कमी है, इसके अलावा ट्रैफिक कोन टूट हुए हैं और इस मार्ग पर दबाव के कारण अल्टावा, परियोजना के लिए बनाया गया है।

इसलिए साइकिल ले जाने वाले छात्रों के साथ दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि देश की बनाने के लिए लगाए गए कई सूरत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा 'साइकिल टू स्कूल' के पायलट प्रोजेक्ट के लिए सिटी लाइट क्षेत्र में स्कूल कीलों से साइकिल चलाने वाले विद्यार्थियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इसके अलावा, ट्रैफिक कोनों से निकली गए ट्रैफिक सेस की कमी है, इसके अलावा ट्रैफिक कोन टूट हुए हैं और इस मार्ग पर दबाव के कारण अल्टावा, परियोजना के लिए बनाया गया है।

इसलिए साइकिल ले जाने वाले छात्रों के साथ दुर्घटना की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि देश की बनाने के लिए लगाए गए कई सूरत स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड द्वारा 'साइकिल टू स्कूल' के पायलट प्रोजेक्ट के लिए सिटी लाइट क्षेत्र में स्कूल कीलों से साइकिल चलाने वाले विद्यार्थियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं। इसके अलावा, ट्रैफिक कोनों से निकली गए ट्रैफिक सेस की कमी है, इसके अलावा ट्रैफिक कोन टूट हुए हैं और इस मार्ग पर दबाव के कारण अल्टावा, परियोजना के लिए बनाया गया है।

ब्रांड एक वादा होता है और एक अच्छा ब्रांड वादा निभाने में विश्वास रखता है

क